पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सौमित्र सिंह और अन्य

बनाम

हरे राम सिंह और अन्य

2022 की प्रथम अपील सं. 7

19 नवंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

यथास्थिति प्रदान करने के लिए प्रार्थना।

हेडनोट्स

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XXXIX नियम 1 और 2—अस्थायी निषेधाज्ञा—वाद की भूमि मूल रैयत (मृतक) की थी, अपीलकर्ताओं ने खुद को मूल रैयत (मृतक) का वंशज होने का दावा किया—प्रतिवादी 2 सेट ने भी खुद को मूल रैयत (मृतक) का वंशज होने का दावा किया—अपीलकर्ता मूल रैयत के साथ अपने संबंध को साबित करने में विफल रहे—विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं और मूल रैयत (मृतक) के बीच विवादित संबंध पर कोई मुद्दा नहीं बनाया, जो अपीलकर्ताओं के दावे का आधार था—अपील को मुकदमे की निरंतर प्रक्रिया मानी जाती है—अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे में विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले के पारित होने के बाद, मुकदमे की भूमि का कुछ हिस्सा प्रतिवादियों द्वारा कई बिक्री पत्रों के माध्यम से कई व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

निर्णीत: यदि किसी "मुकदमा" या "वाद" को न्यायनिर्णयन के लिए स्वीकार कर लिया गया है तो मुकदमे की विषय-वस्तु को सुरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है ताकि उसे अंतिम न्याय निर्णयन के समय उपलब्ध कराया जा सके—मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को मुकदमे की भूमि हस्तांतरित करने से रोक दिया गया था और तात्कालिक अपील मुकदमे की निरंतरता है—अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया है, प्रतिवादियों को अपील के लंबित रहने के दौरान मुकदमे की शेष भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है—प्रतिवादियों

को अपील के लंबित रहने के अवधि में न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे की शेष संपत्ति को दूसरों के हस्तांतरित करने, स्वामित्व बदलाव करने और भारग्रस्त करने से रोका गया — आई.ए. को अनुमति दी गई। **(पैराग्राफ 12 और 13)**

न्याय दृष्टान्त

महरवाल खेवाजी ट्रस्ट (पंजीकृत), फरीदकोट बनाम बलदेव दास, एआईआर 2005 एससी 104; देव प्रकाश एवं अन्य. बनाम इंद्रा एवं अन्य, (2018) 14 एससीसी 292; धर्म नाथ ओझा एवं अन्य। बनाम रघुनाथ ओझा, (2001) 2 पीएलजेआर 268—पर भरोसा किया गया।

बेस्ट सेलर्स रिटेल **(इंडिया)** प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड और अन्य, **(2012) 6** एससीसी **792**—संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908

मुख्य शब्दों की सूची

प्रथम अपील; स्थानांतरण, अन्यसंक्रामण; भारग्रस्त, रैयत; विक्रय विलेख।

प्रकरण से उत्पन्न

अंतर्वर्ती आवेदन 2022 की प्रथम अपील संख्या 07

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री जे.एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता; श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों के लिए: श्री शशि शेखर द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री पार्थ गौरव, अधिवक्ता; श्री गोविंद राज शाही, अधिवक्ता; श्री मनोज्ञा सिंह, अधिवक्ता।

हेडनोट्स रिपोर्टर द्वारा बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 की प्रथम अपील सं. 7

==========

1. सौमित्र सिंह, पिता-स्वर्गीय कुमार बिमल प्रसाद सिंह, निवासी, गाँव-रजौली, डाकघर और पुलिस थाना-रजौली, जिला-नवादा ।

2. आशा सिंह उर्फ़ आशा देवी, पति-स्वर्गीय सुमंत कुमार सिंह, निवासी, गाँव-रजौली, डाकघर और पुलिस थाना-रजौली, जिला-नवादा।

3. किस्ले किशोर, पिता-स्वर्गीय सुमंत कुमार सिंह, निवासी, गाँव-राजौली, डाकघर और पुलिस थाना-रजौली, जिला-नवादा।

4. प्रेम शंकर शरण सिंह, पिता-स्वर्गीय उमा शंकर शरण सिंह, निवासी, गाँव-रजौली, डाकघर और पुलिस थाना --राजौली, जिला-नवादा ।

5. दिवाकर प्रसाद सिंह, पिता-स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह, निवासी, गाँव-रजौली, डाकघर और पुलिस थाना -रजौली, जिला-नवादा।

अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. हरे राम सिंह, पिता-श्री कृष्ण सिंह उर्फ कृष्ण देव सिंह, निवासी, गाँव-रजौली, बभांतोली, डाकघर और पुलिस थाना-रजौली, जिला-नवादा।

2. श्रीमती. द्रोपति देवी, पति-कृष्णा सिंह उर्फ कृष्ण देव सिंह, निवासी, गाँव-राजौली, बभांतोली, डाकघर और पुलिस थाना-रजौली, जिला-नवादा ।

3. सिया राम सिंह, पिता-कृष्ण सिंह उर्फ कृष्ण देव सिंह, निवासी, गाँव-रजौली, बभांतोली, डाकघर और पुलिस थाना -रजौली, जिला-नवादा।

4. अजीत कुमार, पिता-चंद्रदीप सिंह, निवासी, गांव-देवासपुरा, डाकघर-बाघी, पुलिस थाना - कतरीसराय, जिला-नालंदा ।

प्रतिवादी प्रथम सेट-प्रतिवादी प्रथम सेट

5. राम प्रवेश सिंह, पिता-हरिहर सिंह, निवासी, गांव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना - गिरियक, जिला-नालंदा।

6. बालीमिकी सिंह, पिता-हरिहर सिंह, निवासी, गांव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना - गिरियक, जिला-नालंदा।

7. संजय प्रसाद, पिता-स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह, निवासी, गाँव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना -गिरियक, जिला-नालंदा।

8. रंजीत प्रसाद, पिता-स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह, निवासी, गांव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना -गिरियक, जिला-नालंदा।

9. मंजय प्रसाद, पिता-स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह, निवासी, गांव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना -गिरियक, जिला-नालंदा।

10. बिपिन कुमार, पिता-स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह, निवासी, गांव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना -गिरियक, जिला-नालंदा।

11. नवीन कुमार, पिता-स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद सिंह, निवासी, गांव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना-गिरियक, जिला-नालंदा।

12. श्रीमती मणि देवी, पति-श्री बच्चू सिंह, निवासी, गाँव-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना - गिरियक, जिला-नालंदा ।

13. रबी देवी, पति-मुंद्रिका सिंह, निवासी, ग्राम-पुरी, डाकघर-पावापुरी, पुलिस थाना-गिरियक, जिला-नालंदा।

14. मंजू देवी, पति-सुरेन्द्र कुमार, निवासी, गाँव-अमझारी, डाकघर और पुलिस थाना -सिरदलला, जिला - नवादा।

प्रतिवादी द्वितीय सेट-उत्तरदाता द्वितीय सेट

प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री जे. एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता,

श्री राकेश के. आर, एड.

उत्तरदाताओं के लिएः श्री शशि शेखर द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री पार्थ गौरव, अधिवक्ता।

श्री गोविंद राज शाही, अधिवक्ता।

श्री मनोग्या सिंह, अधिवक्ता।

==========

कोरमः माननीय न्यायाधीश श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

13 19-11-2024 **संदर्भः 2022 की आई.ए. सं. 1**

वर्तमान अंतरिम आवेदन अपीलकर्ताओं की ओर से दायर किया गया है, जिसमें प्रतिवादियों को मुकदमे की संपत्ति को स्वामित्व बदलाव करने और भारग्रस्त करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा के माध्यम से यथास्थिति का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है, साथ

ही वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान मुकदमे की संपत्ति की भौतिक संरचना को बदलने से रोकने की भी प्रार्थना की गयी है।

2. मुकदमा लंबित रहने के दौरान, संबंधित भूमि की कुछ संपत्तियां भी बेच दी और इस प्रकार, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने और मुकदमे की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति का आदेश पारित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसे दिनांक 14.03.2019 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.05.2019 के आदेश द्वारा निषेधाज्ञा के उक्त आदेश को वापस ले लिया गया । दिनांक 30.05.2019 के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ताओं/वादी ने इस न्यायालय के समक्ष विविध अपील संख्या 397/2019 के तहत एक अपील प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई हुई और निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना दिनांक 13.05.2020 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उस अपील में 02.09.2019 को आदेश सुरक्षित रखा गया था और अंततः 13.05.2020 को निर्णय सुनाया गया था और इस बीच की अवधि के दौरान प्रतिवादियों/प्रतिवादियों ने विभिन्न बिक्री विलेखों के माध्यम से मुकदमे की भूमि के कुछ हिस्सों को फिर से स्थानांतरित कर दिया।

3. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादियों/प्रतिवादियों ने 2020 के एसएलपी संख्या 8280 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांकित 13.05.2020 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विविध मामलों में पारित इस न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। अपील सं. 397/2019 और परिणाम में, उक्त एस. एल. पी. को खारिज कर दिया गया और इन सभी से तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि वाद की भूमि को वाद के लंबित रहने के दौरान बदला या अलग नहीं किया जाना चाहिए था और यह एक स्थापित कानून है कि एक अपील को वाद की निरंतरता माना जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित

निर्णय के पारित होने के बाद, प्रत्यर्थियों ने फिर से वाद भूमि का हस्तांतरण करने के लिए आगे बढ़े और वाद भूमि के कुछ हिस्सों के संबंध में कई बिक्री विलेखों को निष्पादित किया और बिक्री विलेखों की प्रतियां पूरक हलफनामे के साथ दायर की गई हैं और यही यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि उत्तरदाता अन्य व्यक्तियों के पक्ष में वाद भूमि में स्वामित्व हस्तांतरित रखने में बहुत रुचि रखते हैं और यदि उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमे या वाद होने की बहुत संभावना है।

4. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि मुकदमे के किसी भी पक्ष को मुकदमे की प्रकृति को स्थानांतरित या अलग करके बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इस तरह के हस्तांतरण से पक्ष को नुकसान या क्षति हो सकती है जो अंततः सफल हो सकता है और आगे कई कार्यवाहियों का कारण बन सकता है।इस निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। **महारवाल खेवाजी ट्रस्ट (विनियमित), फरीदकोट बनाम बलदेव दास ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 104** में रिपोर्ट किया गया है और जिस प्रासंगिक पैराग्राफ पर निर्भरता रखी गई है, उसे तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> *"**10.** चाहे जो भी हो, श्री सच्चर का यह तर्क देना सही है कि जब तक और जब तक मुकदमे के किसी पक्ष द्वारा अपूरणीय क्षति या क्षति का मामला नहीं बनाया जाता है, तब तक अदालत को संपत्ति की प्रकृति को बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसमें संपत्ति का अलगाव या हस्तांतरण भी शामिल है जिससे पक्ष को नुकसान या क्षति हो सकती है जो अंततः सफल हो सकता है और आगे कई कार्यवाहियों का कारण बन सकता है।तत्काल मामले में अपूरणीय क्षति का ऐसा कोई मामला नहीं बनता है सिवाय इस तर्क के कि कानूनी कार्यवाही में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए, प्रतिवादी को अनुसूचित संपत्ति का बेहतर उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नहीं सोचते हैं कि निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने*

प्रत्यर्थी को निर्माण करके संपत्ति की प्रकृति को बदलने की अनुमति देने के साथ-साथ संपत्ति के हस्तांतरण की अनुमति देने में न्यायसंगत था, चाहे जो भी शर्तें हों जिन पर ऐसा किया जाता है। अपीलार्थी के दावे के अंततः आधारहीन पाए जाने की स्थिति में, यह प्रतिवादी के लिए हरजाने का दावा करने के लिए हमेशा खुला है या, एक उपयुक्त मामले में, अदालत स्वयं इस में हुए नुकसान, यदि कोई हो, के लिए हरजाने का फैसला कर सकती है। ध्यान दें। चूँकि इस मामले के तथ्य प्रत्यर्थी को निर्माण करने और उसे अलग करने की अनुमति देने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं बनाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि नीचे की दोनों अदालतों, अर्थात् निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश देने में गलती की।उक्त आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और निचली अदालत के आदेश को बहाल किया जाता है।

"अपीलार्थियों के अधिवक्ता के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त सिद्धांत **देव प्रकाश और अन्य बनाम इंदिरा और अन्य** के मामले में इसका अनुपालन किया गयाथा जो **(2018) 14 एस. सी. सी. 292** में रिपोर्ट कियागया है ।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि किसी मुकदमे को निर्णय के लिए स्वीकार किया गया है तो यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह मुकदमे के विषय-वस्तु को एक उचित आदेश द्वारा संरक्षित करे ताकि वह अंतिम निर्णय के समय उपलब्ध हो और डिक्री बंजर न हो। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **धरम नाथ ओझा और अन्य बनाम रघुनाथ ओझा** के मामले में **(2001) 2 पीएलजेआर 268** में रिपोर्ट किया गया है में पारित इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जिस प्रासंगिक अनुच्छेद पर निर्भरता रखी गई है, उसे तैयार संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है : "के प्रतिद्वंद्वी पर विचार करने के बाद

प्रस्तुतियाँ, मेरा विचार है कि इस आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। कानून अच्छी तरह से तय है कि यदि किसी मुकदमे को

निर्णय के लिए स्वीकार किया गया है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह मुकदमे की विषय वस्तु को एक उचित आदेश द्वारा संरक्षित करे ताकि वह अंतिम निर्णय के समय उपलब्ध हो और डिक्री बंजर न हो जाए।दूसरा, "।

6. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक, अर्थात्, रोहन सिंह अपीलकर्ताओं के एक सामान्य पूर्वज थे, जिनके दो बेटे थे, अर्थात् बैद्यनाथ सिंह और मोदन सिंह और वादी बैद्यनाथ सिंह की शाखा से हैं और कन्हई सिंह मोदन सिंह की शाखा से थे, जिनकी बिना किसी विवाद के मृत्यु हो गई, जबकि बचाव पक्ष ने मुकदमे की संपत्तियों में अधिकार का अपना दावा करने के लिए कन्हई सिंह की एक अलग वंशावली स्थापित की थी और उक्त कन्हई सिंह की वंशावली मुख्य प्रश्न था, लेकिन इस संबंध में, विद्वान निचली अदालत द्वारा कोई मुद्दा तैयार नहीं किया गया था और मामले पर चर्चा किए बिना। साक्ष्यों के अनुसार, विद्वत निचली अदालत ने कहा कि वादी मूल रैयत कन्हई सिंह के साथ अपने संबंधों को साबित करने में विफल रहे, जबकि बचाव पक्ष के दूसरे सेट राम प्रवेश सिंह और अन्य ने कन्हई सिंह के साथ अपने संबंधों को स्थापित किया। लेकिन उक्त निष्कर्ष निकालते समय, साक्ष्य की कोई चर्चा नहीं की गई। इस प्रकार, दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत राहत पाने के योग्य बनाने के लिए जिन तीन मुख्य तत्वों को पूरा करना आवश्यक है, वे सभी इस मामले में पूर्ण हैं।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शशि शेखर द्विवेदी प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं दिखाई है कि *प्रथम दृष्टया* मामला उनके पक्ष में मौजूद है और इस संबंध में, पैराग्राफ संख्या 8.25 और 8.26 में विवादित फैसले में विद्वान निचली अदालत का निष्कर्ष प्रासंगिक है। वर्तमान याचिका में, अपीलकर्ताओं ने केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक विभिन्न न्यायालयों द्वारा मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निषेधाज्ञा के लिए अपीलकर्ताओं की प्रार्थना को अनुमति देने या अस्वीकार करने के इतिहास का उल्लेख किया है जो एक निश्चित निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता है कि क्या कोई प्रथम दृष्टया मामला अपीलकर्ताओं के पक्ष में बनाया गया है या नहीं। अपीलकर्ताओं ने

अपने दावे को स्वर्गीय कन्हई सिंह के रिश्तेदार होने के रूप में आधारित किया, लेकिन वे विद्वत निचली अदालत के समक्ष अपनी कथित अभिवचन के समर्थन में कोई सबूत पेश करने में विफल रहे और यहां तक कि विद्वत निचली अदालत को मुकदमे की संपत्ति पर अपीलकर्ताओं का कब्जा भी नहीं मिला। हालाँकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थियों के पक्ष में एक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि अपीलार्थियों का मुकदमा 2022 (13) का पटना उच्च न्यायालय एफ. ए. संख्या 7 है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, इसलिए, केवल इस अपील के कारण, प्रत्यर्थियों को विवादित निर्णय और डिक्री के फल से दूर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल अपील दायर करने से किसी मामले में पारित निर्णय और डिक्री का प्रभाव निलंबित नहीं होता है। मान लीजिए, मुक़दमे की ज़मीन एक स्वर्गीय कन्हई सिंह की थी और इसके अलावा, मान लीजिए, उनकी बिना किसी विवाद के मृत्यु हो गई और बचाव पक्ष के दूसरे पक्ष ने स्वर्गीय कन्हई सिंह के रिश्तेदार होने के कारण उक्त कन्हई सिंह के सभी अंतिम संस्कार किए और विवादित संपत्ति पर कब्जा कर लिया।

8. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता बहुत छोटे व्यक्ति और वादी हैं और विवादित भूमि के स्थान से उनकी निकटता का लाभ उठाते हुए, उन्होंने प्रतिवादियों के कब्जे को परेशान करना शुरू कर दिया, इस कारण से, उक्त प्रतिवादियों ने सोचा कि इसे बेचना बुद्धिमानी होगी क्योंकि सूट की भूमि उनके घर से दूर थी और अंत में, उन्होंने विभिन्न बिक्री विलेखों को निष्पादित करके सूट भूमि का कुछ हिस्सा प्रतिवादियों को बेच दिया, जो उसी पर कब्जे में आए हैं और उनके पक्ष में उत्परिवर्तन की भी अनुमति दी गई है।

9. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि केवल 2022 (13) डी. टी. के पटना उच्च न्यायालय एफ. ए. संख्या 7 द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के पक्ष में एक शीर्षक बनाना। इस अपील के लंबित रहने के दौरान यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलकर्ताओं के पक्ष में निषेधाज्ञा देने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है क्योंकि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है

कि अपील का निर्णय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार भी हस्तांतरणकर्ता पर बाध्यकारी होगा और अपीलार्थी अब यह दावा करने के हकदार नहीं हैं कि यदि मुकदमा भूमि दूसरों को हस्तांतरित की जाती है तो उन्हें एक अपूरणीय क्षति होगी। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान समय में, पहली अपील पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लेने में कई साल लगते हैं, इसलिए, यदि उत्तरदाताओं को मुकदमे की भूमि को अलग करने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित या वर्जित किया जाता है, तो यह उन्हें विवादित निर्णय और डिक्री के फल से वंचित कर देगा जो उनके पक्ष में हैं और यदि अपीलकर्ताओं की प्रार्थना की अनुमति दी जाती है तो वे हारने वाले की स्थिति में आ जाएंगे।

10. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***बेस्ट सेलर्स रिटेल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड और अन्य,*** **(2012) 6 एस. सी. सी. 792** में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, तथा जिस अनुच्छेद पर भरोसा किया गया है, उसे तत्काल संदर्भ हेतु उदद्धृत किया जा रहा है :

> *"29. फिर भी, कानून का तय सिद्धांत यह है कि जहां भी प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, अदालत अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर देगी यदि को चोट लगी है। अस्थायी निषेधाज्ञा से इनकार करने के कारण वादी को हुई पीड़ा अपूरणीय नहीं थी।*
>
> *30. दलपत कुमार और अन्न बनाम प्रह्लाद सिंह और अन्य। [(1992) 1 एस. सी. सी. 719] इस न्यायालय ने निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पी. 721, पैरा 5)*
>
> > *"5. ... यह संतुष्टि कि अपने आप में एक प्रथम दृष्टया मामला है, निषेधाज्ञा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप राहत मांगने वाले पक्ष को 'अपूरणीय क्षति' होगी और निषेधाज्ञा देने के अलावा पक्ष के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है और उसे अनुमानित चोट या विस्थापन के परिणामों से सुरक्षा की आवश्यकता है। हालाँकि, अपूरणीय चोट का मतलब यह नहीं है कि चोट की*

मरम्मत की कोई शारीरिक संभावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब केवल यह है कि चोट एक भौतिक होनी चाहिए, अर्थात्, जिसे नुकसान के रूप में पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।"

11. दोनों पक्षों को सुना और विवादित फैसले, दोनों पक्षों की दलीलें और निचली अदालत के मामले के रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों का अध्ययन किया। वाद भूमि निर्विवाद रूप से स्वर्गीय कन्हई सिंह की थी।वादी, जो यहाँ अपीलकर्ता हैं, अपने दावे को इस आधार पर आधारित करते हैं कि वे स्वर्गीय कन्हई सिंह के वंशज हैं, जबकि प्रतिवादी दूसरा समूह (5 से 9) खुद को स्वर्गीय कन्हाई सिंह का वंशज होने का दावा कर रहे हैं।

12.प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं ने अपने पक्ष में *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनाया है, क्योंकि वादी/अपीलकर्ता मूल रैयत कन्हाई सिंह के साथ अपने संबंध को साबित करने में विफल रहे हैं और इस संबंध में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है और यहां तक कि उनके पास मुकदमे की भूमि पर भौतिक कब्जा भी नहीं पाया गया है और इस संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पैराग्राफ संख्या 8.25, 8.26 और 8.42 में की गई टिप्पणियां प्रासंगिक हैं। यद्यपि उक्त पैराग्राफ में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां अपीलकर्ताओं के दावे के विरुद्ध हैं, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी और स्वर्गीय कन्हाई सिंह के बीच विवादित संबंध पर कोई मुद्दा नहीं बनाया, जो वादी के दावे का आधार था और उक्त पैराग्राफ में उन साक्ष्यों की विस्तृत चर्चा नहीं है, जिन पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष आधारित किए और यह बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि पैराग्राफ संख्या 8.1 में विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित संबंध को मुख्य मुद्दा माना, लेकिन फिर भी इस बिंदु पर कोई विशेष मुद्दा नहीं बनाया गया, इसलिए केवल विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से यह नहीं माना जा सकता कि वादी/अपीलकर्ताओं ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनाया है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील को मुकदमे की एक निरंतरता प्रक्रिया माना जाता है। यद्यपि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर वाद को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन केवल इस तथ्य से यह नहीं माना जा

सकता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद अंतिम हो गया है क्योंकि यह अभी भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन/लंबित है और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का इस न्यायालय द्वारा मुख्य प्रश्नों का निर्धारण करते समय पुनः मूल्यांकन किया जाना है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वादी द्वारा दायर वाद में विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के पारित होने के बाद, वाद की भूमि का कुछ हिस्सा प्रतिवादियों द्वारा कई बिक्री विलेखों के माध्यम से कई व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया है और इस संबंध में, अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा विशिष्ट विवरण दिए गए हैं और कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई वाद न्यायनिर्णयन के लिए स्वीकार किया गया है तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह मुकदमे की विषय-वस्तु को संरक्षित करे ताकि अंतिम न्यायनिर्णयन के समय उसे उपलब्ध कराया जा सके। प्रतिवादियों के पिछले आचरण को देखते हुए, प्रतिवादियों द्वारा शेष वाद भूमि को अन्य के पक्ष में हस्तांतरित करने की बहुत अधिक संभावना है, जो दोनों पक्षों सहित कई व्यक्तियों के बीच वादों की बहुलता का कारण हो सकता है और यदि इस अपील के लंबित रहने के दौरान शेष वाद भूमि को हस्तांतरण के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो अंतिम निर्णय के बंजर हो जाने की संभावना है और यदि अपीलकर्ता सफल होते हैं तो उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को वाद भूमि हस्तांतरित करने से रोक दिया गया था और तत्काल अपील वाद की निरंतरता है और केवल इस तथ्य से कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर वाद खारिज कर दिया गया है, प्रतिवादियों को इस अपील के लंबित रहने के दौरान शेष वाद भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं मिलता है।

13. यद्यपि इस अपील पर अंतिम रूप से निर्णय होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन केवल इस कारण से इस अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी /उत्तरवादियों द्वारा मुकदमे की भूमि को हस्तांतरण के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि प्रतिवादियों को मुकदमे की भूमि को हस्तांतरित या स्वामित्व बदलाव करने से रोका जाता है, तो इससे उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय के अवलोकन के अनुसार मुकदमे की भूमि उनके कब्जे में बताई गई है, जबकि दूसरी ओर, मुकदमे की शेष भूमि के हस्तांतरण के कारण अपीलकर्ताओं को बहुत असुविधा हो सकती है, क्योंकि वे मुकदमे की भूमि पर अपना स्वामित्व दावा कर रहे हैं और

तदनुसार, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, सुविधा का संतुलन अपीलकर्ताओं के पक्ष में है। इस प्रकार, यह न्यायालय वादी/अपीलकर्ताओं की प्रार्थना में सार पाता है, इसलिए, प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं को इस अपील के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे की शेष संपत्ति को दूसरों के पक्ष में हस्तांतरित, स्वामित्व बदलाव करने और भारग्रस्त करने से रोका जाता है। प्रतिवादी-उत्तरवादियों को इस न्यायालय के समक्ष वाद भूमि के किसी भी भाग को हस्तांतरित करने के लिए प्रार्थना करने की स्वतंत्रता होगी, यदि तत्काल और कानूनी आवश्यकता उनके पक्ष उत्पन्न होती है जो ऐसे हस्तांतरण की आवश्यकता को उचित ठहराती है।

14. नतीजतन, आई ० ए० संख्या : 1/ 2022 स्वीकृत की जाती है।

<u>संदर्भ :2022 की प्रथम अपील सं. 7</u>

15. इस अपील को उचित शीर्षक के अंतर्गत यथासमय सूचीबद्ध करें।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायाधीश)

अन्नु

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।